

सं० ओ० वि०/एफ.डी./49-86/19083.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज विविध पोली पैकेजिंग, 14/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राजा राम वर्मा मार्फत राष्ट्रीय मजदूर संघर्ष यूनियन (रजि०), प्लॉट नं० ए-408, टुल रूम ट्रेनिंग सेंटर के सामने औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राजा राम वर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/55-86/19089.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज विविध पोली पैकेजिंग 14/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कृष्ण गोपाल मार्फत राष्ट्रीय मजदूर संघर्ष यूनियन (रजि०), प्लॉट नं० ए-408, टुल रूम ट्रेनिंग सेंटर के सामने औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली-110052 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

* और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री कृष्ण गोपाल, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे. पी. रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

ORDER

The 7th June, 1986

No. 7475/153-WA.—Whereas the land described in the Haryana declaration No. 2432/153-WA, dated 11th March, 1986 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, Haryana for a public purpose, namely, for the Construction of Bidhrana Sub-Minor taking off at RD 67795-Left Sirsa Parallel Distributory from RD 0 to 6116 in village Bhana Brahman and Shimla in Tehsil Narwana, District Jind.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, Irrigation Branch, Ambala to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid notification.

By order of the Governor of Haryana.

M. P. VACHHER,
Superintending Engineer,
Bhakra Canal Circle,
Kaithal.